



कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
"प्रकीर्ण वर्ग"



लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून

Phone & Fax:- 0135-2530467, 2530431 Website-<http://pwd.uk.gov.in> E-Mail-eicpwduk@nic.in

पत्रांक:- 164 / 174 / ए.प्र. - प्रकीर्ण / 10

दिनांक: 17 / 2 / 2018

:: परिपत्र ::

दिनांक 01-07-2017 से GST लागू होने के पश्चात पूर्व में गठित अनुबन्धों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु जारी शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांक 05-09-2017 में दिये गए निर्देशों के क्रम में खंडों में कार्यरत फील्ड अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ताओं द्वारा समय समय पर इस कार्यालय को पत्र प्राप्त हुए हैं, जिनमें की गयी पृच्छाओं के निराकरण हेतु निम्नवत दिशानिर्देश जारी किए जा रहे हैं:-

- 1- उपरोक्त शासनादेश में GST लागू होने के पश्चात, पूर्व में गठित अनुबन्धों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के संबंध में फील्ड अभियन्ताओं द्वारा प्रक्रिया को सरलीकृत करने हेतु माँग की गयी है। जिसके संबंध में स्पष्ट करना है कि उक्त शासनादेश वाणिज्य कर विभाग द्वारा GST की गाइडलाईन के अनुसार तथा वित्त विभाग की सहमति से शासन द्वारा जारी किया गया है, जो कि लोक निर्माण विभाग के साथ ही प्रदेश के अन्य विभागों पर भी लागू है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय लोक निर्माण विभाग (Office Memorandum No. SE/TAS/GST/13 dated 02-01-2018) तथा अन्य राज्यों में जैसे लोक निर्माण विभाग, उत्तरप्रदेश (शासनादेश स 1614/23-10-2017-12(सामान्य)/2017 दिनांक 09-11-2017) द्वारा भी उक्त शासनादेश के समान ही व्यवस्था दी गयी है। अतः केंद्र, अन्य प्रदेश व राज्य स्तर पर अपनाई जा रही प्रक्रिया के अतिरिक्त केवल उत्तराखण्ड लोक निर्माण विभाग के लिए अलग से प्रक्रिया का निर्धारण ओचित्यपूर्ण प्रतीत नहीं होता है।

अतः निर्देशित किया जाता है कि पूर्व में गठित अनुबन्धों में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया हेतु शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांक 05-09-2017 में दिये गए निर्देशों के अनुसार ही कार्यवाही की जाय।

- 2- फील्ड अभियन्ताओं द्वारा भवन कार्यों के आगणन में GST जोड़ने की प्रक्रिया हेतु निर्देश चाहे गए हैं। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि भवन कार्यों में दरे केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किए जाने वाले DSR से ली जाती है। वर्तमान में केंद्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी DSR में मदों की भाषा के अनुसार दरे समस्त लागू करों को जोड़कर प्राप्त है, अतः DSR के मदों से गठित आगणनों में GST हेतु अलग से कोई राशि नहीं जोड़ी जानी है।
- 3- खंडों में कार्यरत फील्ड अभियन्ताओं, अधीक्षण अभियन्ताओं तथा क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा सुझाव दिया गया है कि लोक निर्माण विभाग द्वारा पूर्व के वर्षों के जारी केंद्रीय एस०ओ०आर० को पुनरीक्षित कर बिना TAX की दरे निकालकर पुनः केंद्रीय एस०ओ०आर० जारी किए जाय। इस संबंध में खंड स्तर पर गणना केवल 1 जुलाई से पूर्व के गठित अनुबन्धों के संबंध में कुछ मदों की ही, संबन्धित ब्लाक हेतु की जानी है। परंतु यदि केंद्रीय स्तर पर गणना की जाती है तो प्रत्येक वर्ष के लगभग 1.50 लाख मदों की गणना की जानी होगी जो कि अव्यवहारिक है। अतः सम्यक विचारोपरांत निर्देशित किया जाता है कि गणना का कार्य शासनादेश के अनुसार खंड स्तर से ही किया जाएगा।
- 4- कतिपय खंडों द्वारा अवगत कराया गया है कि कुछ प्रकरणों में शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांक 05-09-2017 में दी गयी प्रक्रिया के अनुसार गणना ऋणात्मक होने कारण देयक कि धनराशि कम हो रही है। इस प्रकार के प्रकरणों में भी शासनादेश के अनुसार ही कार्यवाही की जानी है।
- 5- कुछ अभियन्ताओं द्वारा पूर्व के वर्षों के सामग्री में सम्मिलित टैक्स की दरे इस कार्यालय से जारी किए जाने हेतु माँग की गयी है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि इस कार्यालय द्वारा केंद्रीकृत SOR जारी किए जाते समय सामग्री की फील्ड अभियन्ताओं द्वारा उपलब्ध कराई गयी बाजारी दरों के अनुसार SOR गठित किया जाता है, तथा बाजारी दरे तत्समय लागू समस्त टैक्स को सम्मिलित मानते हुए ली जाती है। जिस कारण विभिन्न सामग्री पर तत्समय लागू टैक्स की दरे इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। पूर्व के वर्षों के विभिन्न सामग्री में लागू वैट की दरे वाणिज्य कर विभाग तथा एक्साइज टैक्स की दरे केंद्रीय सीमा एवं उत्पाद शुल्क विभाग से या इन विभागों की वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। वेबसाइट की जानकारी शासनादेश स० 2137/III(2)/17-27(सामान्य)/2017 दिनांक 05-09-2017 में दी गयी है।

क्रमशः...

- 6- खंडो मे कार्यरत फीलड अभियन्ताओं द्वारा अवगत कराया गया है कि पूर्व के वर्षों के एसओआर के दर विश्लेषण फीलड अभियन्ताओं के पास उपलब्ध नहीं है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि पूर्व के वर्षों (वर्ष 2011-12 से वर्ष 2016-17 तक) के एसओआर PWIMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से जारी किए गए हैं, वैबसाइट <http://202.91.91.120> पर उपलब्ध है, एवं वर्ष 2016-17 के Misc SOR की दर विश्लेषण रिपोर्ट तथा वर्ष 2017-18 कि समस्त SOR रिपोर्ट वैबसाइट <http://pwdsor.pwduk.in/> पर उपलब्ध है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दर विश्लेषण के आधार पर ही एसओआर की दरें आगणन में ली जाती है, साथ ही कार्य करते समय कार्य स्थल पर गुणवत्ता नियंत्रण हेतु विभिन्न सामग्री की आवश्यकता, देयक में रायल्टी की गणना, अतिरिक्त मद की दर निर्धारित करने आदि के लिए फीलड अभियन्ता के पास मद का दर विश्लेषण होना अत्यंत आवश्यक है। दर विश्लेषण रिपोर्ट तकनीकी स्वीकृति हेतु गठित आगणन का अभिन्न भाग है। अतः भविष्य के लिए निर्देशित किया जाता है कि तकनीकी स्वीकृतकर्ता अधिकारी, तकनीकी स्वीकृत आगणन में मदों की दर विश्लेषण रिपोर्ट आवश्यक रूप से लगाया जाना सुनिश्चित करे।

- 7- खंडो मे कार्यरत फीलड अभियन्ताओं द्वारा यह भी आशंका व्यक्त की गयी है कि खंड स्तर पर GST की गणना JE / AE द्वारा की जा रही है तथा भविष्य में किसी गलती के संज्ञान में आने पर समस्त ज़िम्मेदारी संबन्धित JE / AE की मानी जाएगी। इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि उपखंड से प्राप्त देयकों में GST की गणना को भुगतान से पूर्व प्राविधिक वर्ग तथा लेखा वर्ग से विस्तृत परीक्षण सुनिश्चित होने के पश्चात ही भुगतान किया जाय।

(एच० के० उप्रेती)

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग
देहरादून

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सलगनों सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखंड शासना
2. मुख्य अभियन्ता स्तर I (मुख्यालय), विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
3. समस्त मुख्य अभियन्ता, क्षेत्रीय कार्यालय लो0 नि0 वि0, उत्तराखण्ड देहरादून/ पौड़ी/टिहरी/हल्द्वानी/पिथौरागढ/अल्मोड़ा
4. मुख्य अभियन्ता USRIP/ UEAP/ UDRP देहरादून।
5. वित्त नियंत्रक विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
6. वरिष्ठ स्टाफ आफिसर्स I / II विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
7. समस्त अधीक्षण अभियन्तावाँ वृत्त लो0 नि0 वि0
8. निदेशक क्वालिटी कंट्रोल, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लो0 नि0 वि0 देहरादून।
9. अधिशासी अभियन्ता IT को विभागीय वेब साइट पर अपलोड करने हेतु।
10. समस्त अधिशासी अभियन्ता, प्रा०/नि०/ अस्थायी/ रा० मा० खंड
11. समस्त तकनीकी स्टाफ, विभागाध्यक्ष कार्यालय, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।

प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष
उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग
देहरादून